ब्रिटेन के प्रीमियम बाजार अब भारतीय किसानों के लिए खुल जाएंगे...भारत और यूके के बीच व्यापार
देशों के निर्यातकों को मिलने वाले लाभ के समान या उससे भी अधिक फायदा मिलेगा। इससे भारतीय

भारतीय किसानों के लिए खुल जाएंगे ब्रिटेन के प्रीमियम बाजार

2030 तक 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य को पाने में मिलेगी मदद

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) से भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। समझौते से कृषि निर्यात को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के भारत के बड़े लक्ष्य भी पूरा करने में मदद मिलेगी।

यह समझौता भारतीय कृषि क्षेत्र को उच्च मात्रा से उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने की तरफ मोड़ेगा। इससे किसान स्थानीय मांग को पूरा करने के साथ वैश्विक बाजारों की जरूरतें भी पूरी करने की तरफ बढ़ सकेंगे। इसके साथ ही, भारत ने इस समझौते से देश के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं और ब्रिटेन को डेयरी उत्पादों, सेब, जई एवं खाद्य तेलों पर टैरिफ रियायत नहीं देने का फैसला किया है। इससे इन क्षेत्रों के घरेलू किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा।

कृषि के अलावा खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पाद क्षेत्र भी इस समझौते से लाभ उठा सकेंगे। समझौते में श्रम प्रधान क्षेत्रों को भी बड़ी राहत दी गई है। समुद्री उत्पादों पर 20 फीसदी, वस्त्रों पर 12 फीसदी, रसायनों पर आठ फीसदी और धातुओं पर 10 फीसदी तक का शुल्क अब नहीं लगेगा।

इस समझौते के लागू होने के बाद भारत की 95 फीसदी से अधिक कृषि वस्तुएं और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद ब्रिटेन में बगैर किसी शुल्क के जाएंगे। आने वाले तीन साल में ब्रिटेन को भारत से होने वाले कृषि निर्यात में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इनमें फल, सब्जियां, अनाज, मसाला मिश्रण, फलों के गूदे और तैयार भोजन आदि शामिल हैं। इससे ब्रिटेन में इन चीजों की पहुंच लागत कम हो जाएगी, जिससे ये उत्पाद वहां मुख्यधारा और पारंपरिक खुदरा शृंखला दोनों में बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में 99.7 फीसदी उत्पादों पर शुल्क 70 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

नए उभरते उत्पादों के लिए अवसर : कटहल, बाजरा जैसा मोटा अनाज, सब्जियां, जैविक जड़ी-बूटियां जैसे उत्पाद यूके बाजार में उतर सकेंगे। इससे भारत के किसान फसल विविधीकरण कर पाएंगे और घरेलू कीमतों में उतार-चढ़ाव से बच पाएंगे।

शराब उद्योग को राहत : शराब और खाद्य उत्पादों जैसे उत्पादों के निर्यात-आयात के क्षेत्र के ब्रिटेन के क्यूडीटी एनालिटिक्स के निदेशक, शिवलकर परमानंदम ने कहा, भारत में शराब आयात पर 150 फीसदी टैक्स था, जो अब घटेगा।

समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन। एजेंसी

प्रतिस्पर्धा में बढ़ेगी भारत की ताकत

इस समझौते से प्रमुख देशों में भारत को प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

भारतीय कृषि उत्पादों को जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय निर्यातकों के साथ टैरिफ समानता मिलेगी।

वस्त्र और चमड़े पर शून्य शुल्क से बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के बीच भारत की प्रतिस्पर्धा की ताकत बढ़ेगी।

अगले दो वर्षों में भारत के चमड़ा क्षेत्र को ब्रिटेन में 5% की अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का अनुमान है।

आईटी पेशेवरों से लेकर मत्स्य क्षेत्र और निर्यात के मोर्चे पर लाभ

आईटी पेशेवर : सामाजिक सुरक्षा अंशदान में तीन साल तक छूट

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत से ब्रिटेन को होने वाले निर्यात में श्रम आधारित उद्योगों में 23 अरब डॉलर के नए मौके पैदा होंगे। इससे दोनों ही देशों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। वहीं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत भारत के आईटी पेशेवरों को तीन साल तक ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। यह भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। ऐसे पेशवरों की संख्या 75,000 है जबकि नियोक्ताओं की संख्या करीब 900 है।

मत्स्य क्षेत्र : जबरदस्त बढ़ावा

समझौता खासतौर से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों के मत्स्य उद्योग को फायदा पहुंचाएगा। 99% झींगा, टूना, मछली का भोजन और चारा जैसे समुद्री उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं। यह शुल्क मौजूदा वक्त में 4.2 फीसदी से 8.5 फीसदी तक है।

ब्रांडेड चाय-कॉफी को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय ब्रांडेड उत्पाद जैसे कॉफी,चाय, मसाले और पेय पदार्थों के निर्यात में बड़ा अवसर मिलेगा। अभी ब्रिटेन को 1.7% कॉफी, 5.6% चाय और 2.9% मसाले निर्यात होते हैं। अब इनका निर्यात तेजी से बढ़ेगा। अब भारत की इंस्टेंट कॉफी ब्रिटेन में जर्मनी और स्पेन जैसे बड़े यूरोपीय ब्रांड्स को टक्कर दे सकेगी।

शिल्प : विरासत को मिलेगा सम्मान

भारत का वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र महिलाओं के कौशल पर टिका है। चाहे वह वह कांचीपुरम, भागलपुर, जयपुर या वाराणसी की बुनकर, कढ़ाई, रंगाई करने वाली या डिजाइनर हों। अब वे वैश्विक फैशन और डिजाइन की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर पाएंगी।

कोल्हापुरी चप्पल : लगेंगे वैश्विक पंख

महाराष्ट्र और आस-पास के इलाकों में हाथ से बनाई जाने वाली कोल्हापुरी चप्पलें अब प्रीमियम बाजार में बगैर शुल्क बिक सकेंगी। इससे ब्रांड बढ़ेगा। संस्कृति सुरक्षित रहेगी। आय बढ़ेगी और टिकाऊ चमड़े के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात होगा दोगुना

समझौते के बाद भारत से ब्रिटेन को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग निर्यात 2030 तक दोगुना होने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में रासायनिक उत्पादों का निर्यात 30 से 40 फीसदी बढ़ सकता है। रत्न और आभूषण निर्यात अगले तीन वर्षों में वर्तमान 94.1 करोड़ डॉलर से दोगुना होने की उम्मीद है। व्यापार समझौते के प्रभावी होने के बाद सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में सालाना 20 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है, समझौते से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करने में मदद मिल सकती है।